भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 482
मंगलवार, 03 फरवरी, 2026/14 माघ,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियाँ

482. **श्री भुमरे संदिपनराव आसाराम:**
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में आज की तिथि में कार्यरत प्राथमिक, जिला और शीर्ष सहकारी समितियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) उक्त राज्यों को सहकारी क्षेत्र सुधार और डिजिटलीकरण योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता की राशि कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्यों में और विशेषकर सूखा प्रभावित जिलों में डेयरी, चीनी और कृषि सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार, दिनांक 20.01.2026 तक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में क्रमशः कुल 2,26,006 और 53,950 सहकारी समितियां हैं । महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों, जिला परिसंघों और राज्य परिसंघों की क्षेत्रवार संख्या क्रमशः **संलग्नक -1** और **संलग्नक -2** में संलग्न है ।

(ख) दिनांक 25.01.2026 तक, एनसीडीसी ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए संचयी रूप से 5,10,955.14 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किए गए कार्यकलाप -वार संवितरण को **संलग्नक -3** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को जारी की गई निधियों की स्थिति **संलग्नक -4** के रूप में संलग्न है।

(ग) सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से "सहकार-से-समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में डेयरी, चीनी और कृषि-सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों में शामिल हैं:

i. आदर्श उप-विधियाँ जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों, उनके प्रचालन में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। अब, पैक्स पीएम-किसान समृद्धि केंद्र (PMKSKs), प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJKs), कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि के रूप में कार्य कर सकते हैं।

ii. सहकारी नेतृत्व वाली "श्वेत क्रांति 2.0" का उद्देश्य सहकारी कवरेज, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण का विस्तार करना है, जिसका उद्देश्य "अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध प्रापण को मौजूदा स्तर से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना, वंचित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाना है।

iii. सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि अप्रैल 2016 से सहकारी चीनी मिलों को किसानों को उचित और लाभकारी या राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य तक उच्च गन्ना मूल्य का भुगतान अतिरिक्त आयकर के अधीन नहीं होगा ।

iv. सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में एक प्रावधान किया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत देते हुए व्यय के रूप में अपने भुगतान का दावा करने की अनुमति दी गई है।

v. सरकार ने एनसीडीसी के माध्यम से एथेनॉल संयंत्र या कोजेनरेशन सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने अथवा कार्यशील पूंजी के लिए या तीनों उद्देश्यों के लिए एक योजना शुरू की। मंत्रालय ने योजना के तहत एनसीडीसी को 1000 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये) जारी किए हैं और एनसीडीसी ने 56 सहकारी चीनी मिलों को 10,005 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

vi. सहकारिता मंत्रालय के सुझावों पर इंडियन पोटाश लिमिटेड ने बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए पहल की है।

******

संलग्नक -1

महाराष्ट्र में क्षेत्रवार प्राथमिक समितियां, जिला परिसंघ और राज्य परिसंघ

क्रम सं.	क्षेत्र	समितियों की संख्या	जिला परिसंघ	राज्य परिसंघ
1	कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति	3,618	3	0
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	5,556	7	1
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	1	0	0
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	1,980	2	0
5	क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट समिति	20,835	12	4
6	डेयरी सहकारी समिति	13,364	8	0
7	शैक्षिक और प्रशिक्षण सहकारी समितियां	70	12	1
8	मात्स्यिकी सहकारी समिति	3,401	6	3
9	हस्तशिल्प सहकारी समिति	13	0	0
10	हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	509	2	2
11	आवासन सहकारी समिति	1,27,485	24	0
12	जूट और कॉयर सहकारी समिति	13	0	0
13	खादी ग्रामोद्योग समिति	3	0	0
14	श्रमिक सहकारी समिति	11,506	27	0
15	पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति	623	0	0
16	विपणन सहकारी समिति	1,341	2	0
17	विविध ऋण सहकारी समिति	322	3	0
18	विविध गैर क्रेडिट	7,474	24	2
19	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	4,812	2	0
20	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS)	21,233	0	0
21	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	3	0	0
22	सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी	469	0	0
23	चीनी मिल सहकारी समिति	99	0	1
24	पर्यटन सहकारी समिति	127	0	0
25	परिवहन सहकारी समिति	241	0	0
26	आदिवासी-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति	15	0	1
27	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	454	4	1
28	महिला कल्याण सहकारी समिति	439	0	0
	कुल	**2,26,006**	**138**	**16**

स्रोत: दिनांक 20.01.2026 तक एनसीडी पोर्टल के अनुसार

<u>**संलग्नक -2**</u>

मध्य प्रदेश में क्षेत्रवार प्राथमिक समितियां, जिला परिसंघ और राज्य परिसंघ

क्रम सं.	क्षेत्र	समितियों की संख्या	जिला परिसंघ	राज्य परिसंघ
1	कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति	3,628	15	1
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	1,750	0	0
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति		0	0
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	4,978	1	1
5	क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट समिति	3,541	0	0
6	डेयरी सहकारी समिति	10,632	0	0
7	शैक्षिक और प्रशिक्षण सहकारी समितियां		4	2
8	मात्स्यिकी सहकारी समिति	2,979	0	0
9	हस्तशिल्प सहकारी समिति		0	0
10	हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	895	0	0
11	आवासन सहकारी समिति	3,042	0	1
12	जूट और कॉयर सहकारी समिति		0	0
13	खादी ग्रामोद्योग समिति		0	0
14	श्रमिक सहकारी समिति	1,136	0	0
15	जूट और कॉयर सहकारी समिति		0	0
16	विपणन सहकारी समिति	358	0	1
17	विविध ऋण सहकारी समिति		0	0
18	विविध गैर क्रेडिट	1,820	7	1
19	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	1,767	0	0
20	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS)	5,207	0	0
21	रेशम उत्पादन सहकारी समिति		0	0
22	सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी		1	0
23	चीनी मिल सहकारी समिति		0	0
24	पर्यटन सहकारी समिति		0	1
25	परिवहन सहकारी समिति	184	0	0
26	जनजातीय-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति	37	0	0
27	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)		0	0
28	महिला कल्याण सहकारी समिति	11,526	0	0
	कुल	**53,950**	**28**	**8**

स्रोत: दिनांक 20.01.2026 तक एनसीडी पोर्टल के अनुसार

संलग्नक -3

पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र में एनसीडीसी द्वारा संवितरण (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना /कार्यकलाप	वर्ष 2025-26 25.01.2026 के अनुसार	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	कुल
1	विपणन	3.75					**3.75**
2	डेयरी और पशुधन				0.33	3.98	**4.31**
3	उपभोक्ता					0.90	**0.90**
4	एफपीओ	2.88	2.57	2.24	0.53	0.36	**8.58**
5	मात्स्यिकी	7.55	11.31	14.09	10.52	0.10	**43.57**
7	सी, आईसी तथा एससी	15.00	81.06	36.40	6.40	7.70	**146.56**
8	चीनी	2,224.25	7,617.50	2,004.34	686.65	653.84	**13,186.58**
9	वस्त्र	16.71	51.31	44.35	46.72	21.19	**180.28**
10	एम.आई.एस		0.75				**0.75**
	कुल	**2270.14**	**7764.50**	**2101.42**	**751.15**	**688.07**	**13575.28**

पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में एनसीडीसी द्वारा संवितरण (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना /कार्यकलाप	वर्ष 2025-26 25.01.2026 के अनुसार	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	कुल
1	विपणन और इनपुट	1,028.00					**1,028.00**
2	वस्त्र				20.00		**20.00**
3	डेयरी और पशुधन	0.05	0.09	0.04			**0.18**
4	एफ एंड वी		0.20	0.07			**0.27**
5	खाद्यान्न		0.12				**0.12**
6	तिलहन	0.04	0.23	0.08			**0.35**
7	एफपीओ	1.39	2.49	2.76	2.06	0.43	**9.13**

8	**मात्स्यिकी**	0.32	0.38	0.72	0.44	0.04	**1.90**
9	**भंडार**	0.29	1.13	0.94	0.85	0.97	**4.18**
10	**सी, आईसी तथा एससी**	215.99	291.33	310.06	245.05	455.00	**1,517.43**
11	**चीनी**		30.00	8.00	7.60		**45.60**
12	**सीएसआर**				0.01	0.01	**0.02**
13	**आईसीडीपी**			0.20	8.40	20.64	**29.24**
	कुल	**1246.08**	**325.97**	**322.87**	**284.41**	**477.09**	**2656.42**

संलग्नक -4

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को पिछले 3 वर्षों के लिए जारी की गई निधियां (20.01.2026 तक)

करोड़ में

क्रम सं.	राज्य का नाम	2025-26	2024-25	2023-24	कुल
1	महाराष्ट्र	9.13	0	33.64	42.78
2	मध्य प्रदेश	7.77	0	25.42	33.20